

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 618 राँची, शुक्रवार,

8 पौष, 1939 (श०)

29 दिसम्बर, 2017 (ई॰)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना 2 मार्च, 2017

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत निवारण तंत्र को विकसित करने हेतु रू. 2,00,00,000.00 (दो करोड़) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या - खा.प्र.-01/रा.खा.सु.(जी.आर.एम.)/07-01/2017 - 924-- राज्य में माह अक्टूबर, 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू की गई है। यह अधिनियम लाभुकों को भोजन का अधिकार प्रदान करती है। अधिनियम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लाभुकों को ससमय निर्धारित मात्रा में निर्धारित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करायी जाय।

2. इस अधिनियम में निहित प्रावधानानुसार राज्य की 86.48% ग्रामीण जनसंख्या एवं 60.20% शहरी जनसंख्या को आच्छादित किया जाना है। उक्त परिपेक्ष्य में वर्तमान में इस अधिनियम के अन्तर्गत 2,63,68,731 लाभुकों को आच्छादित किया जा चुका है जो कि 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 80% है। राज्य के इतनी बड़ी लाभुक आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना राज्य सरकार के समक्ष एक महती चुनौती है। लाभुकों की इतनी बड़ी संख्या एवं इनके बसावट को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि खाद्यान्न प्राप्ति करने में कितपय लाभुकों को

दिक्कतें आ सकती हैं । इन दिक्कतों/कठिनाईयों के निराकरण हेतु एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र होना अत्यंत आवश्यक है ताकि लाभुकों की समस्याओं/शिकायतों इत्यादि का अल्पाविध में सफलतापूर्वक निवारण किया जा सके ।

- 3. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत Internal Grievance Redressal Mechanism, Tollfree/Helpline no., नोडल पदाधिकारी का पदाभिहित किया जाना, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी की नियुक्ति/पदाभिहित किया जाना तथा राज्य खाद्य आयोग के गठन/पदाभिहित करने का प्रावधान है।
- 4. अधिनियम में उल्लेखित उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में विभाग द्वारा कई कार्य किये गये हैं। उक्त परिपेक्ष्य में विभागीय स्तर पर जन शिकायत निवारण कोषांग का गठन किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय स्तर पर Tollfree/Helpline no. एवं Public Grievance Management System (PGMS) का संचालन किया जा रहा है। साथ ही पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत नोडल पदाधिकारी के रूप में तथा अपर समाहर्त्ता को संबंधित जिला के जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की नियमावली तैयार कर ली गई है एवं इसके गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- 5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु विभाग द्वारा कई कदम उठाये जा चुके हैं। शिकायतों के त्वरित एवं निश्चित समयाविध में निवारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए इस व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। साथ ही इसके अतिरिक्त अन्य मदो में भी व्यय संभावित है।
- 6. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में शिकायत निवारण तंत्र के लिए रू. 2,00,00,000.00 (दो करोड़) मात्र का बजटीय उपबंध (बजट शीर्ष 3456-सिविल पूर्ति, 41-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शिकायत निवारण, 07-अन्य व्यय, 54-एकम्श्त प्रावधान) प्राप्त है।
- 7. उक्त परिपेक्ष्य में शिकायत निवारण तंत्र को विकसित एवं क्रियान्वयन करने हेतु उपबंधित राशि रू. 2,00,00,000.00 (दो करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे, सरकार के सचिव।
